जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 36 संख्याः 274 प्रभात अजमेर, बुधवार 13 मई, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

घाटगेट स्थित एसओजी ऑफिस में नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम पहुंची। एसओजी ने सीकर व जयपुर से लगभग 150 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स व कोचिंग संस्थान के संचालकों से पूछताछ करके 15 स्टूडेंट्स को डिटेन किया है उनको सीबीआई टीम के सुपुर्द किया जाएगा। क्योंकि नीट की परीक्षा रद्द करके सीबीआई को जांच सौंपी गई हैं। एसओजी में पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लाम्बा ने मीडिया को जानकारी दी। आरपीएससी सदस्य शिव सिंह राठौड़ को भी एसओजी ने पूछताछ के बाद जाने दिया। राठौड़ ने जाते समय मीडिया से बातचीत की।

पेपर लीक के कारण नीट परीक्षा रद्द

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। नेशनल टैस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 3 मई को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा कथित पेपरलीक के बाद रद्द कर दी गई है। इस कथित पेपर लीक के कारण लगभग 22 लाख छात्र प्रभावित हुए।

केन्द्र ने यह भी घोषणा की कि देश की सबसे बड़ी अंडरग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा पुनः आयोजित की जाएंगी, जिसकी तारीखें बाद में सूचित की जाएगी। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

एक बयान में नेशनल टैस्टिंग एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय केन्द्रीय एजेंसियों के समन्वय में प्राप्त जानकारी की समीक्षा के बाद लिया गया, और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई जांच रिपोर्टों ने परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए।

- **नैशनल टैस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की कि नए सिरे से परीक्षा के लिए जल्दी ही कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।**

छात्रों और अभिभावकों को हुई असुविधा को स्वीकार करते हुए, एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री के नाम पर कांग्रेस में अनिश्चितता, भाजपा को भा रही है?

भाजपा को अभी तक भारी प्रयासों के बावजूद सफलता हासिल नहीं हो पाई थी केरल में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। आठ दिन हो गए हैं, कांग्रेस ने राज्य में भारी बहुमत जीतकर केरल में 10 साल के वाम शासन का अंत किया, लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा।

कई दौर की बैठकों के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया। देर रात, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से दिल्ली वापस बुलाया गया, तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व फिर से बैठक में जुट गया।

पार्टी नेतृत्व के.सी. वेणुगोपाल, जिनके पास अधिक संख्या में विधायक हैं, और पार्टी नेता सतीशन, जिनके पास केरल में व्यापक बाहरी समर्थन और कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल का समर्थन है, के बीच फंसा हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी वह बात नहीं समझ रहे है जो सबको पता है कि अगर के.सी. वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यह कांग्रेस के भीतर विद्रोह को जन्म दे सकता है, जिससे राज्य में लंबे समय तक भाजपा को दूर रखने वाला माहौल बदल सकता है।

बताया गया है कि के.सी. वेणुगोपाल ने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा है कि राहुल ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या नहीं। वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव से पहले राहुल को राज्य में हो रही गतिविधियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **भाजपा प्रसन्न है कि अगर वेणुगोपाल को मु.मंत्री बनाया गया तो केरल में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ज्यादा दिन अपनी निराशा पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तथा भाजपा को पैर जमाने का मौका मिल जाएगा।**
- **वेणुगोपाल ने पार्टी के संगठन मंत्री होने के कारण, पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट बाँटे थे। अतः प्रथम दृष्टया, विजयी विधायक, आँख की शर्म के कारण वेणुगोपाल के साथ दिखते हैं। पर, विधानसभा में विपक्ष के नेता सतीशन, जमीनी स्तर पर ज्यादा लोकप्रिय हैं तथा उनकी शिकायत है कि जब वेणुगोपाल दिल्ली में ''पावर पोलिटिक्स'' कर रहे थे, तब वे केरल में कार्यकर्ताओं के बीच काम में जुटे थे। ऐसी स्थिति में अगर वेणुगोपाल मु.मंत्री बनाये जाते हैं तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, अपनी निराशा पर ज्यादा दिन नियंत्रण नहीं रख पाएगा और भाजपा को पैर पसारने का आसान रास्ता मिल जाएगा।**

अमेरिका, पाकिस्तान की ''तटस्थता'' को संदेह की दृष्टि से देख रहा है?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। अमेरिका-ईरान संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका वॉशिंगटन में जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रम्प प्रशासन के कुछ वर्गों को शक है कि इस्लामाबाद एक खतरनाक दोहरा खेल खेल रहा है, एक ओर वो सार्वजनिक तौर पर तो कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है, जबकि दूसरी ओर पर्दे के पीछे कथित तौर पर तेहरान की मदद कर रहा है।

यह अविश्वास तब और बढ़ गया, जब खबर आई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह संदेश पाकिस्तान के माध्यम से भेजा था, जिसने हाल ही में अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी की थी। सी.एन.एन. की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प के निकट कई अधिकारी मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। वे यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इस्लामाद ने बातचीत में आई रुकावट को लेकर वॉशिंगटन की नाराज़गी को तेहरान तक सही-सही पहुँचाया था।

यह चिंता उस समय और बढ़ गई, जब सी.बी.एस. न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी सैन्य विमानों को रावलपिंडी के नूर खान एयर बेस का उपयोग करने की अनुमति दे दी।

- **अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान, तेहरान से सहानुभूति रखता है तथा उसने ईरान की सेना के विमानों को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को काम में लेने की छूट भी दी थी, जिससे ईरान के विमानों को अमेरिका की ''एयर स्ट्राइक'' से बचाया जा सके।**

ऐसा करके उसने संभवतः उन विमानों को संभावित अमेरिकी हवाई हमलों से बचाया, जबकि इस्लामाबाद दुनिया के सामने खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था।

दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सी.बी.एस. ने बताया कि ट्रम्प द्वारा अप्रैल की शुरुआत में ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद, तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान भेजे, जिनमें ईरानी वायु सेना का आरसी-130 टोही विमान शामिल था। यह लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस का निगरानी और खुफिया संग्रहण संस्करण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान ने कुछ नागरिक विमान अफगानिस्तान स्थानांतरित किए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उनमें सैन्य उपकरण शामिल थे या नहीं।

इन आरोपों के कारण अमेरिकी प्रशासन के कुछ हिस्सों में अविश्वास बढ़ गया है। वहाँ के अधिकारियों को अब लगने लगा है कि शायद पाकिस्तान वॉशिंगटन के रूख को तेहरान तक मजबूती से नहीं पहुँचा रहा है, जिससे ईरानी नेतृत्व में बातचीत के भविष्य को लेकर अलग-अलग व्याख्याएँ उभर रही हैं।

यह मतभेद तब खुलकर सामने आया, जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने तेहरान की भविष्य की रणनीति को लेकर चुनौतीपूर्ण रुख अपनाया।

उन्होंने कहा, ''अब हमारे पास विभिन्न विकल्प हैं, या तो हम सम्मान, अधिकार और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठें और ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को प्राप्त करें, या हम ''न युद्ध, न शांति'' की स्थिति में रहें, या हम युद्ध और टकराव के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।

उन्होंने कहा कि ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन केवल सैन्य ताकत और राष्ट्रीय गरिमा की स्थिति के साथ।

उन्होंने आगे कहा, ''तर्कसंगत, तार्किक और राष्ट्रीय हित पर आधारित प्राथमिकता यह है कि जो जीत सशस्त्र बलों ने युद्धक्षेत्र में प्राप्त की, वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट पेपर लीक- नासिक का प्रिंटिंग प्रेस संचालक गिरफ्तार

नासिक, 12 मई। मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा 2026 की प्रश्नपत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के नासिक का कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में नासिक स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक की संलिप्तता उजागर हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

यह जानकारी नासिक पुलिस आयुक्तालय के क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त किरण चव्हाण, सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके और परिमंडल दो के पुलिस उपायुक्त किशोर काले ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी।

जांच में सामने आया है कि प्रश्नपत्र नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था। इसके बाद इस प्रश्नपत्र के हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, बिहार और केरल जैसे राज्यों तक पहुंचने के संदिग्ध रास्ते भी उजागर हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है तथा और भी लोगों से पूछताछ की संभावना है।

- **प्रश्नपत्र नासिक की प्रेस में छपा, फिर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार व केरल भेजा गया।**

'अगले दो साल भारी कंस्ट्रक्शन व ''डिमोलेशन'' पर प्रतिबंध हो'

नीति आयोग ने पश्चिमी एशिया की स्थिति के कारण, ''बैल्ट टाइट'' करने के ठोस कदम सुझाए

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। कठोर वित्तीय नियंत्रण की नीति तेजी से लागू होती नजर आ रही है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों को ईंधन खर्च कम करने, सोना खरीदना बंद करने और ''कोविड जैसी स्थिति'' के लिए तैयार रहने की सलाह दिये जाने के बाद, नीति आयोग, जो केन्द्र सरकार का थिंक टैंक है, ने एक सलाह जारी की है, जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को रोकने का सुझाव दिया गया है।

यदि यह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो जिन भवनों के निर्माण/तोड़फोड़ के कार्य चल रहे हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा, जैसे निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन आदि। ये गतिविधियाँ मोदी सरकार की सैन्ट्रल विस्टा को फिर से डिजाइन करने की योजना का हिस्सा हैं।

ऐसा लगता है कि इस सलाह के माध्यम से, नीति आयोग पश्चिम एशिया संकट और तेल आपूर्ति में व्यवधान के कारण आवश्यक कठोर वित्तीय माहौल बनाने की तैयारी कर रहा है। निर्माण/तोड़फोड़ की गतिविधियों के लिए भारी मशीनरी, गैस कटर, क्रशर, क्रेन और बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है और सबसे महत्वपूर्ण, ईंधन की जरूरत होती है। पश्चिम एशिया संकट द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए, नीति आयोग ने इन गतिविधियों को दो वर्षों के लिए रोकने की सिफारिश की है।

प्रधानमंत्री की कठोर वित्तीय अपील का विपक्षी नेताओं और आम नागरिकों द्वारा सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया है, जिन्होंने चुनाव प्रचार और अन्य कार्यक्रमों में सरकार के व्यय के मामलों को उजागर किया है। नेटिज़न्स ने प्रधानमंत्री के उस रोड शो पर भी सवाल उठाए, जो उन्होंने 10 मई को हैदराबाद में नागरिकों को वित्तीय अनुशासन की सलाह देने के तुरंत बाद आयोजित किया। उस अवसर पर लगभग 100 कारों का काफिला प्रधानमंत्री के साथ चला, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता लगभग 50 वाहनों के काफिले के साथ जा रहे थे। प्रधानमंत्री के शुक्रवार से शुरू होने वाले पांच देशों के दौरे को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई है।

नीति आयोग की यह सलाह नागरिकों और विपक्षी नेताओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकने का प्रयास भी प्रतीत होती है, क्योंकि यह सार्वजनिक खर्च में भी रोक का सुझाव देती है।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अशोक लाहिड़ी हैं, जिन्हें हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लाहिड़ी एक अर्थशास्त्री हैं और 2021 से 2026 तक बलूरघाट निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल विधानसभा के भाजपा सदस्य रहे हैं।

- **नीति आयोग की यह हिदायत स्वीकार कर ली गई तो दिल्ली में निर्माण भवन, उद्योग भवन और शास्त्री भवन पर कंस्ट्रक्शन गतिविधि पूर्णतया स्थगित कर दी जाएगी।**
- **पर, इन सार्वजनिक भवनों का पुनर्निर्माण मोदी सरकार की ''सैंट्रल विस्टा'' को पुनः डिज़ायन करने की महत्वाकांक्षी योजना का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।**

आज हो सकता है केरल के मु.मंत्री का फैसला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। कांग्रेस पार्टी केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा संभवतः मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह कर सकती है।

राहुल गांधी ने 10 जनपथ में केरल के पार्टी नेताओं के साथ बैठकों में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के समर्थन में अधिक समर्थन पाया। मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्य मुकाबला सतीशन और वेणुगोपाल में है, जबकि तीसरे उम्मीदवार रमेश चेनिथला ने खुद को हटा लिया, क्योंकि उन्हें पूर्व राज्य अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों का समर्थन नहीं मिला।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व व्यापक परामर्श ले रहा है, क्योंकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **कांग्रेस पार्टी में 10 जनपथ पर भारी विचार मंथन चल रहा है।**

भारत ने रूस के एलएनजी सप्लाई को अस्वीकार किया

भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका की नाराज़गी का जोखिम नहीं उठाना चाहता

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की नाराज़गी से बचने के स्पष्ट कदम के रूप में, मोदी सरकार ने कथित तौर पर रूस के लिक्विफाइड नैचुरल गैस (एलएनजी) बेचने के प्रस्ताव को अस्वीकार दिया, जो अमेरिका के प्रतिबंधों के तहत था, जबकि मध्य पूर्व में तनाव के कारण आपूर्ति में कमी थी।

एक एलएनजी जहाज, जो भारत में आने वाला था, अब फंसा हुआ है क्योंकि नई दिल्ली ने रूस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है।

एक उच्च स्तरीय सूत्र ने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के शीर्ष निर्णय निर्माता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल शामिल हैं, ट्रम्प के गुस्से से डर रहे हैं और देश हित में निर्णय लेने की स्वतंत्रता छोड़ने तक के लिए तैयार हैं।

दो सूत्रों, जिनको इस मामले की प्रत्यक्ष जानकारी है, ने रॉयटर्स को बताया कि भारत के लिए निर्धारित रूस के एक टैंकर को लटका कर रखा गया है, स्वीकृत कार्गो पर बातचीत चल रही है। जबकि मध्य एशिया के तनाव के कारण, ऊर्जा-आपूर्ति जबरदस्त रूप से प्रभावित है।

भारत का रुख इस बात को उजागर करता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित एलएनजी कार्गो की खरीद टालने के बीच कितनी सावधानी से संतुलन साध रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि मॉस्को की अपने एलएनजी निर्यात को नए बाज़ारों में स्थानांतरित कर सकने की क्षमता सीमित है।

एक सूत्र ने बताया कि भारत की हिचकिचाहट के कारण, रूस के बाल्टिक सागर स्थित यूएस प्रतिबंधित पोर्टोवाया प्लांट से एक एलएनजी कार्गो अनलोड नहीं हो सका, जबकि इसे अप्रैल के मध्य में भारत पहुँचना था। आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जहाज को ट्रैक किया गया, जबकि दस्तावेज़ इस बात का संकेत दे रहे थे कि कार्गो गैर-रूसी था।

रॉयटर्स ने अप्रैल के मध्य में एलएसईजी शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए बताया था कि 1,38,200-क्यूबिक-मीटर क्षमता वाला टैंकर कुनपेंग भारत के पश्चिमी हिस्से के दाहेज इम्पोर्ट टर्मिनल की ओर जा रहा था। एलएसईजी के अनुसार, अब यह जहाज सिंगापुर के पास समुद्र में है और इसका कोई गंतव्य नहीं बताया गया है।

एक सूत्र ने बताया, भारत, रूस का सबसे समुद्री क्रूड तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और भारत ने 30 अप्रैल को रूस के उप ऊर्जा मंत्री पावेल सोरोकिन को इस निर्णय से अवगत किया कि वह प्रतिबंधित एलएनजी नहीं खरीदेगा। उस दौरान सोरोकिन ने भारतीय अधिकारियों, जिनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल थे, से मुलाकात की। यह पिछले कुछ महीनों में उनकी दूसरी बैठक थी, और सोरोकिन जून में पुनः बातचीत के लिए लौट सकते हैं।

भारत के तेल और गैस मंत्रालय और रूस के दिल्ली स्थित दूतावास ने तुरंत टिप्पणी के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

इस बीच, भारत की रूस से क्रूड तेल की खरीद लगातार जारी है, जिसे फरवरी 28 से शुरू हुए अमेरिका-इज़रायल युद्ध के कारण ऊर्जा संकट से निपटने में मदद करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिली है।

आर्कटिक एलएनजी 2 रूस का दूसरा निर्यात प्लांट है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। अमेरिका ने 2025 की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के एलएनजी प्लांटों पर प्रतिबंध बढ़ा दिए।

एक सूत्र ने बताया, जहाजों के माध्यम से क्रूड तेल को छुपाया जा सकता है, लेकिन एलएनजी शिपमेंट को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **जैसा कि विदित ही है, अमेरिका ने रूस से एलएनजी के खरीद पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा रखा है।**
- **इसी कारण से रूस का जहाज जो भारत के लिए एलएनजी लेकर रवाना हुआ था, भारत के बंदरगाह दाहोज पर अपना माल उतारने के लिए, अपना माल नहीं उतार पाया और अब सिंगापुर के आस-पास भटक रहा है।**

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 दुबारा सितंबर को होगी

अजमेर, 12 मई (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का पुनः आयोजन 20 सितंबर 2026 (रविवार) को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे।

आयोग के अनुसार, भर्ती से संबंधित आयु सीमा, आरक्षण, शैक्षिणक योग्यता एवं अन्य सभी शर्तें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी और पत्राचार का पता 16 से 30 मई तक अपडेट कर सकते हैं।**